RAJYA SABHA

Friday, the 29 th November, 1996/8th Agrahayana, 1918 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, *Mr, Chairman* in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: We will finish all the questions today.

Question No. 121 [The Questions (Shri Ram Jethmalani) was absent For answer, vide col. 25 infra]

Expansion of the Net Cultivable Area

122. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

<a) whether it is a fact that the net cultivable area in the country has not increased despite the fact that the technology for the reclamation of salt-affected soils, ravines and water logged soil has been adopted to reclaim such area;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the details of incentives/grants provjded to the State Governments during the last five years in this regard and the results thereof?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में निवल बुवाई वाला क्षेत्र 1950-51 में 1187.50 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1992-93 में 1425.10 लाख हैक्टेयर हो गया।

1985-86 के बाद से क्षारीय, लवण प्रभावित, जलमग्न एवं खादर क्षेत्रों की भूमि को पुन: कृषि योग्य बनाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:-

योजना का नाम	कवर किया गया/ उपचारित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	कवर किए गए राज्य
(1) क्षारीय भूमि के उद्धार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना	4.32	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
(2) क्षारीय भूमि के उद्धार एवं विकास के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई ई सी) से सहायता-प्राप्त योजना	0.08	बिहार और उत्तर प्रदेश
(3) सोडिक भूमि के उद्धार के लिए विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त योजना	0.21	उत्तर प्रदेश
(4) डच सहायता से जलमग्न एवं लवण प्रभावित भूमि के उद्धार के लिए ऑपरेशन पाइलट परियोजना	*	हरियाणा
डकैती से प्रभावित क्षेत्रों में खादर क्षेत्रों का उद्धार	1.27	गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

द एवं सोनीपत जिलों में 2000 हैक्टेयर भूमि को पुन: कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) गत पांच वर्षों में यानि 1991-92 से 1995-96 के दौरान राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता एवं उसके परिणामों का विवरण संलग्न अनुबंध में है।

अनुबंध

1991-92 से 1995-96 के बीच लवण प्रभावित भूमि को पुन: कृषि योग्य बनाने के लिए राज्य सरकारों को दी गई राशि एवं उपलब्धि

(रुपए लाख में)
क्षेत्र हजार हैक्टेयर में

क्रम सं॰	राज्य का नाम	जारी की गई धनराशि	उद्धार की गई भूमि
1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1.	हरियाणा	737.50	67.30
2.	पंजाब	1195.21	97.97
3.	उत्तर प्रदेश	1294.29	71.53
4.	गुजरात	200.80*	-
5.	मध्य प्रदेश	183.50*	-
6.	राजस्थान	26.60*	-
2.	**यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजना**		
1.	उत्तर प्रदेश	1739.37	7.127
2.	बिहार	371.63	0.290
3.	**विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त परियोजना**		
1.	उत्तर प्रदेश	4145.00+	20.545

*1995-96 से धारित

+अगस्त , 1996 तक प्रतिपूर्ति की गई धनराशि

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, जो उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है उसी के आधार पर मैं जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र रोज़गार मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों मंत्रालयों की ओर से कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों मंत्रालयों के बीच में ऐसे कार्यक्रम के लिए कोई समन्वय है, विशेषकर जो वाटर सैट्स के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके कार्यान्वयन में राज्यों की कठिनाइयां हैं, इस संदर्भ में कृषि मंत्रालय ने क्या उपचार किए हैं?

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, यह जो ऐसी भूमि है जो मरूभूमि जैसी है या जिसमें सेलेनिटी ज्यादा है या एलकलाइन ज्यादा है उसको रीकलेम करने में कास्ट तो बहुत है लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से भी, कृषि मंत्रालय की तरफ से भी और दूसरा जो इन्होंने कहा है ग्रामीण विकास से उससे भी करेंगे। हम माननीय सदस्य को सूचित करना चाहेंगे कि अभी जो वर्ल्ड बैंक की टीम आई, उसके अध्यक्ष जो आए, उनसे भी हमने इसकी चर्चा की क्योंकि उन्होंने हमसे कहा कि बढ़ती पापुलेशन के लिए क्या आप सोच रहे हैं तो हमने कहा कि हमारे पास करीब 90 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन है जिसको रीक्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका प्रयास किया जा रहा है।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, सूखा इलाके और मरुस्थल इलाके दोनों की समस्या है इसका तत्काल प्रभाव कृषि उत्पादों पर पड़ता है। इस संबंध में बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष योजना यूरोपियन साझा के अंतर्गत किया गया था। साथ -साथ कृषि मंत्रालय की ओर से 29 स्कीमें और ग्रामीण क्षेत्र मंत्रालय की ओर से 7 राज्यों में ये स्कीमें चलाई जा रही हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से केन्द्र सरकार की सहायता से राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसके समन्वय और निरीक्षण की क्या व्यवस्था सरकार ने सोची है? इसलिए कि मुख्य शिकायत यह आ रही है केन्द्र सरकार की जो सहायता की जा रही है और विशेष कर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो उपयोग किया जा रहा है उसकी कोई समीक्षा समन्वय केन्द्र सरकार से तत्काल किया नहीं जा सका?

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, जब डा॰ मिश्र इस विभाग के मंत्री थे तो दोनों विभाग उन्हीं के अंडर थे। हमारे लिए एक ही है और फिर दूसरा है तो एक और दो में जो फर्क होता उतना फर्क तो अभी होगा ही।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे: ये सब मिश्रित है। दोनों मिश्र की बात है।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: फिर भी हम कहना चाहेंगे कि जिस सवाल को उन्होंने उठाया है, उस को लेकर हमने बार-बार मुख्य मंत्रियों को और बिहार के भी मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है कि...

श्री सतीश अग्रवाल: भूतपूर्व मुख्य मंत्री को भी?

श्री चतुरानन: अभी पूर्व ही रखिए, भूतपूर्व मत करि तो इसीलिए मैं उन को लिख रहा हूं और एम॰पीज॰ को लिखता हूं कि यह-यह योजनाएं हैं - विश्व बैंक की है और सैंट्रली स्पांसर्ड है। मैं ने अपने मंत्रालय में

योजनाओं को कंप्यूटर पर रखा है कि उस की प्रोग्रेस कैसी हो रही है और हरेक तीन महीने बाद वह विभाग से रिपोर्ट मांगते हैं। तो भी ढिलाई बहुत है और आप तो परिचित ही हैं क्योंकि आप मुख्य मंत्री भी रहे हैं। इसलिए वही हाल अभी भी है, थोड़ा सा इधर-उधर है।

SHRI S.M. KRISHNA: Sir, I would like to know whether the hon. Minister denies the statement or the impression that he is carrying that there has been total *ad hocism* with reference to agricultural policies both in the Planning Commission as well as in the Government of India. My information is that he has said that agricultural sector has received a shoddy treatment over the years. Would the hon. Minister clarify to this House as to where exactly does this stand, *vis-a-vis* the impression that he seems to have gained over the last five months as a Minister?

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, the very fact that such a vast area has not been reclaimed itself shows how we are functioning and how we are treating agriculture. What else can I say?

SHRI JIBON ROY: Sir, there is a distinct trend since the process of liberalisation has been initiated in our country. There has been shifting of food producing land to cash crop land. From 1990-91 to 1994-95, around four million hectares of land has been transferred. On the other hand, the yield per hectare has increased only by about 2.5 per cent per annum, just commensurate with the growth of population. As a result of this, according to the Economic Survey Report, between 1990-91 and 1994-95 the availability of food *per capita* has gone down. I would like to know from the hon. Minister as to how the Government's is going to tide over the situation.

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, जैसे दूसरे लोगों को अधिकार है कि जहां ज्यादा इनकम हो उस पेशे का प्यार करें, वैसे ही किसानों को भी अधिकार है कि मिलेगा उस चीज की वह खेती करेंगे। इसीलिए टिंग हो गयी है। अब हमारा काम यह है कि न सफीशिएंट होना चाहिए ताकि हम अपने खिला सकें। इसलिए अगर वह नई फसल और जिस में उन को ज्यादा आमदनी होती है तो म नहीं रोकेंगे। लेकिन अपना उत्पादन बढ़ाकर कैसे भोजन मिल सके, इस की हम गारंटी करते रहेंगे और कुछ विदेश भेजने की भी कोशिश करेंगे जबकि अपने से ज्यादा रहेगा।

श्री जनार्दन यादव: सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बक्सर से लेकर फरक्का तक जो गंगा के किनारे की जमीन का कटाव हो रहा है और अब लगता है कि बक्सर का जो किला है, वह गंगा में चला जाएगा जबकि जमीन तो चली ही गयी है। उस के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, हमारी यही जिम्मेदारी है कि अगर गांव-का-गांव कट गया हो और उस से लोग रिलीफ चाहते हों, तो हम मदद करेंगे। अगर कटाव होता है तो आप को जल-संसाधन मंत्रालय में जाना होगा क्योंकि वह हमारे अधिकार के बाहर है।

श्री एस॰ एस॰ सुरजेवाला: सभापति महोदय, आज के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर छपी है, जिसके बारे में श्री कृष्णा ने सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा, लेकिन मंत्री जी की ओर से उस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। सभापति, महोदय, उस खबर का सारांश यह है कि जो प्लानिंग कमीशन है, उसने कृषि के बारे में पूरी तरह से अनदेखी की है, उसको इग्नोर किया है और प्राथमिकता कृषि को प्लानिंग कमीशन ने अपनी योजनाओं में नहीं दी है। इस पत्र में काफी बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिसमें सिंचाई की योजनाएं हैं, रिकेलेमेशन की बात है, के.वी.के. खोलने की बात है, सोयल टेस्टिंग की बात है। काफी डिटेल में इन्होंने इनकी जो टेक्नोलोजी है, उसकी ओर ध्यान दिलाया है कि प्लानिंग कमीशन ने इनके लिए कोई धनराशि नहीं रखी है। मैं जानना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि क्या मंत्री महोदय उस पत्र को सदन के पटल पर रखेंगे? नंबर वन और नंबर टू, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि उसका सारांश क्या है? कौनसी बात है, जिससे विवश होकर मंत्री जी को स्वयं प्लानिंग कमीशन को, जिसके प्रधानमंत्री खुद अध्यक्ष हैं, उनको यह पत्र लिखना पड़ा। यह बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि पूरा हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि के बारे में अगर खुद कृषि मंत्री चिंतित हैं तो यह सारे सदन के लिए और पूरे देश के लिए गंभीर मसला है। इसलिए इस वक्त जरूरी है कि जल्दी से जल्दी, अर्लिएस्ट ऑपोर्चुनिटी पर मंत्री महोदय इस बात के लिए सदन को अपने कान्फीडेन्स में लें और स्थिति बताएं।

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, इस से तो प्लानिंग कमीशन का सवाल नहीं उठता, यह जो क्वैश्चन है यहां पर। ...(व्यवधान)....

डा॰ जगन्नाथ मिश्र: नहीं, यह जो आपका वक्तव्य आ गया है, उसके मुत्तालिक यह सवाल है। जब आपका वक्तव्य आ गया है तो सदन को पूछने का हक है।

श्री चतुरानन मिश्र: अगर आप कृषि मंत्रालय से पूछते तो हम कह देते, मगर आपने तो पूछा है जमीन के बारे में, रिकेलेमेशन के बारे में और एलक्लेनिटी के बारे में और इस हमारे पत्र में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हां, कुछ लिखा हुआ है। चिंता की बात तो जरूर है।

श्री सतीश अग्रवाल: आपने लिखा है, यह स्टेटमेंट है। That Plan panel is neglecting agriculture ... *(Interruptions)...*

श्री चतुरानन मिश्र: हम कहां न कह रहे हैं। हमने डिनाई नहीं किया है।

श्री सतीश अग्रवाल: हम तो आपको कांपलीमेंट कर रहे हैं कि पहली बार किसी मंत्री ने इतना बोल्ड स्टैण्ड लिया है।

श्री चतुरानन मिश्र: अच्छा, लेकिन इस प्रश्न पर मत कांमलीमेंट कीजिए। दूसरा प्रश्न करके पूछ लीजिए। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री एस॰एस॰ सुरेजवाला: इसका सीधा संबंध है, सर।

श्री चतुरानन मिश्र: नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Shri Gurudas Das Gupta.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, it is interesting to hear the new Agricultural Minister when he says that the peasant has a right to go in for profitable production. But the point is, while it is interesting that he says cultivators can go in for profitable production since profit is the cardinal point,— I am not contesting that—the situation in the country is more serious than what we have-come to know. Food production in the country has gone down to 2.5% last year. While the C.S.O. had estimated that there should be 1% increase in the production of food, it has gone down to 2.5%. As a result, the economic growth .of the country is going to be affected. This is one aspect. Another aspect is, there has been a stupendous increase in the price of essential commodities including rice and wheat. Therefore, in such a situation, while on the one hand, the peasants are going in for profitable production, according to the market law, on the other when, the hon. Minister defends their quest, I would like to know from the hon. Minister what steps the Government would like to take (a) to give inducement to the peasants for producing foodgrains and (b) to bring under cultivation more land which will produce food. Because, it is connected with growth, it is connected with price and it is connected with the living standards of the common people.

श्री चतुरानन मिश्र: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सही है। मैं उससे सहमत हूं कि अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है। मैं पिछले साल के बारे में तो आपको जवाब नहीं दे सकता, ... और न ही उस खेत को फिर से उपजा सकता हूं। अभी के लिए हमने यह किया है कि जो नॉन ग्रीन रिवोल्यूशन एरिया है, उसमें हम कंसन्ट्रेट करना चाहते हैं, वहां की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और इसीलिए हमने यह काम शुरू किया है कि एक तो सारे देश में और सबसे पहले उस एरिया में, जो रेनफेड एरिया है, वहां पूरे, हरेक गांव की जमीन की हम सॉयल टैस्टिंग करवा देना चाहते हैं और डा॰ राजेन्द्र प्रसाद के जन्मदिवस पर बिहार से उस काम को शुरू करेंगे और पूरे उस इलाके का हम सॉयल टैस्टिंग करवा देंगे। किसानों को उनकी जमीन का एक हैल्थ कार्ड मिलेगा कि उसमें कौन से फर्टिलाइज़र की डेफिशिएंसी है, क्या फर्टिलाइज़र देना है, कितना फर्टिलाइज़र देना है और क्या प्रोडक्शन उनका अच्छा हो सकता है।

दूसरा काम हम यह कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन के अंदर विचारार्थ है कि हम तमाम डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक के॰वी॰के॰, कृषि विज्ञान केन्द्र, खोलना चाहते हैं और ऐसा हमने बहुत ज्यादा सरकार से पैसा मांगकर नहीं किया है, अपने बजट को रिकॉस्ट करके हम उसको करने जा रहे हैं, उससे किसानों को सीधे मदद मिलेगी। तो इस तरह वह बहुत बड़ा इलाका जो अभी तक उपेक्षित रहा है या रेनफेड एरिया जिसको आप कहते हैं, जहां प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वहां हम उत्पादन को बढ़ा लेंगे और [illegible] हमारे लिए अन्न का जो सवाल है, वह सस्टेन प्रो[illegible] अपने देश में होने लगेगा और तब पंजाब और [illegible] का बहुत सा उत्पादन हम एक्सपोर्ट भी कर सकें अपने इस इलाके से लेकर के नार्थ-ईस्ट या स[illegible] हम चावल या गेंहूं वगैरह दे सकेंगे। इस कार्य हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए हम प्रपोज़ल [illegible] कमीशन के सामने रख चुके हैं।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I would like to draw the attention of the Agriculture Minister—the concerned Ministry is taking very laudable steps—to three major problems with which we are faced. Will the Government consider setting up a gene bank so that there would be better technology, better growth and better yields and so that it would be cost-effective for the fanners? This is part (a) of my question. Part (b) of my question is this. In order to keep the food crop patterns going and in order to see that India's food buffer-stock doesn't decline, do we have a method of crop patterning? Will the Ministry be able to advise the fanners so that there is no glut of certain crops when the prices go down and there is no thinning out of food crops? The farmers have a right to change to alternative crop patterns. Will the Government consider crop patterning? What incentives would the Government give to those farmers who are going in for traditional crop patterns so that the buffer-stock of India does not get dried up? Part (c) of my question is this. Do you have any incentive scheme for non-conventional crops like saffron? Would you be able to advise the fanners in various parts of the country to grow saffron and other English vegetables, as they are known, like asparagus broccoli avacado? Hybrid quality of seeds should be made available to the fanners.

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, जहां तक जीन बैंक की बात है, करीब एक सप्ताह पहले की बात है कि जीन बैंक का उदघाटन हुआ है और आपने ही उसका उदघाटन किया है और हम यह कह सकते है कि वह विश्व का सबसे बड़ा जीन बैंक हमारे देश में है जहां हमारी केपेब्लिटी एक मिलियन जीन्स रखने की है और हमने यह भी लोगों को आमंत्रित किया है कि इसमें न सिर्फ भारत के बल्कि दूसरे भी जो डेवलपिंग देश हैं, वे भी अगर चाहें तो अपने जीन्स वहां रख सकते हैं और उसमें सहयोग करके उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: 'I the gene bank be available in every region one country?

SHRI CHATURANAN MISHRA: No. It is assible. It is very costly. There will be ene bank. I am asking other countries also me and keep their things there. It will be secert a secret arrangement. But joint operations and joint research will be carried out. Such is the thine.

दूसरा माननीय सदस्या का सवाल है क्रॉप पैटर्न के और हाइब्रिड सीड्स के बारे में, तो यह बहुत गौरव की बात है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, वे लगातार इसका अनुसंधान कर रहे हैं और उन्होंने विश्व स्टैंडर्ड की अपनी ख्याति उपस्थित की है। अब जो हमारे सामने कर्त्तव्य है, वह यह है कि जो उन्होंने रिसर्च किया है, उसको हम गरीबों के या किसानों के फार्म तक कैसे पहुंचाएं, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अगर 50 परसैंट आफ दि रिसर्च को भी हम फार्म पर पहुंचा सके तो हमारा ख्याल है कि देश को परिपूर्ण अनाज मिलेगा, कभी अनाज का संकट नहीं रहेगा।

तो उस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश वैजिटेबल वगैरह के बारे में हमको कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है। अभी भारतीय वैजिटेबल में हम लगे हुए हैं। समय बचेगा तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। उसके एक्सपोर्ट के लिए खास-खास एरिया में हम बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I did not get a reply to my question about the cropping pattern. Will the Government give incentive to farmers to stick to food-crop growth *vis-a-vis* growth of cash crops like flowers or something else?

श्री चतुरानन मिश्र: वह तो हम बराबर दाम बढ़ाकर इंसेंटिव देते हैं। पैसे से बड़ा इंसेंटिव क्या हो सकता है? दूसरी बात यह है कि जहां डिस्ट्रेस सेल की बात आती है, हम तुरंत इंटरवीन करते हैं और उसको खरीद लेते है। फर्टिलाईजर में आपने देखा है कि प्रति बोरा 150 रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी दे रहे हैं और चीजों में भी दे रहे हैं। हम ही दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले से सरकार देती आ रही है। हम भी उसमें थोड़ा घटा-बढ़ाकर दे देते हैं।

Proposed increase in Tuition fee of ITTs

*123. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there will be atleast 15-fold increase in the tuition fees to be charged by the IITs from the next academic session in 1997-98 as reported in "The Times of India", New Delhi edition, dated the 8th November 1996;